इकाई 10 नागरिक समाज संगठनों की भूमिका*

इकाई की रूपरेखा

10.0 उद्देश्य

10.1 प्रस्तावना

10.2 नागरिक समाज का अर्थ, महत्व और भूमिका

10.3 भारत में शक्तिशाली नागरिक समाज आंदोलनों का इतिहास

10.4 सूचना के अधिकार के उद्भव में नागरिक समाज आंदोलनों की भूमिका

10.5 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधिनियमन में सरकार की पहलें

10.6 मूल्यांकन

10.7 निष्कर्ष

10.8 शब्दावली

10.9 संदर्भ लेख

10.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

10.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद, आपः

- भारत में सूचना के अधिकार आंदोलन की उत्पत्ति की चर्चा कर सकेंगे;

* योगदान : प्रो. (डॉ.) प्रीति मिश्रा, विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष, मानवाधिकार विभाग, विधि अध्ययनपीठ, बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

- कानून निर्माण में नागरिक समाज के महत्व और भूमिका की व्याख्या कर सकेंगे;
- सूचना के अधिकार के विकास में नागरिक समाज संगठनों की भूमिका का वर्णन कर सकेंगे;
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधिनियमन में सरकार की पहलों का परीक्षण कर सकेंगे; तथा
- शासन में लोकतांत्रिक सिद्धांतों के मूल्य का वर्णन कर सकेंगे।

10.1 प्रस्तावना

सूचना का अधिकार लोकतंत्र में एक अहस्तांतरणीय अधिकार है। सुशासन और जानने का अधिकार एक दूसरे के पूरक है। सूचना का अधिकार पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करके शासन की गुणवत्ता को बढ़ाता है, जो प्रशासन में लोकतंत्र को शासन की जन–उन्मुख प्रणाली के रूप में माना जाता है। इसे जागरूक, प्रबुद्ध और सशक्त नागरिकों की नींव पर बनाया जाना चाहिए। लोकतंत्र जीवंत हो जाता है, यदि लोग संवैधानिक प्रावधानों, मानवाधिकारों और विकास के अवसरों के बारे में अपनी जागरूकता के आधार पर अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों का दावा करते हैं। सूचना एक संसाधन और साधन है, जो विकास की प्रक्रिया में लोगों की सक्रिय भागीदारी को सुगम बनाता है।

विश्व ने सूचना के अधिकार के लिए एक महान आंदोलन देखा है क्योंकि इसमें शासन के लोकतांत्रिक स्वरूप के सूचनात्मक पहलुओं के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए वैधानिक प्रावधान शामिल हैं। 1946 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मान्यता दी कि, ''सूचना की स्वतंत्रता एक मौलिक मानव अधिकार है और उन सभी स्वतंत्रताओं के लिए कसौटी है, जिनके लिए संयुक्त राष्ट्र को सिखाया गया है।''

इसके तुरंत बाद, सूचना के अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दर्जा दिया गया, जब इसे नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र के अनुच्छेद 19 में निहित किया गया था। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की भावना, 1948, भारत के संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 19 (1)(ए) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देती है। संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है क्योंकि एक नागरिक समाज में सरकारी कार्य पारदर्शी, जवाबदेह और जिम्मेदार होने चाहिए। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का अभिन्न अंग है। सूचना का अधिकार अधिनियम ने भारतीय नागरिकों को लोक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दिया। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया। भारत में वर्तमान सूचना का अधिकार अधिनियम मनमानी और भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों के विरूद्ध दीर्घकाल से चले आ रहे सामूहिक संघर्ष का उत्पाद है।

लोकतंत्र के लिए एक जागरूक नागरिक और सूचना की पारदर्शिता की आवश्यकता होती है, जो इसके कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र की इन विशेषताओं में भ्रष्टाचार होता है और सरकारों और उनके उपकरणों को शासितों के प्रति जवाबदेह ठहराते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, को 15 जून 2005, को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और यह 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियमन ने भारत के संसदीय लोकतंत्र के विकास के एक नए और उच्च स्तर को चिहिनत किया। कानून का अधिनियमन अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों तरह के कई कारकों का परिणाम था। हालांकि संघर्ष लंबा और कठिन था, फिर भी जन आंदोलन सूचना का अधिकार पर कानून बनाने में सफल रहा। भारतीय सूचना का अधिकार अधिनियम के अधिनियमन को व्यापक रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जीत के रूप में दर्ज किया गया है।

वर्तमान इकाई उन परिस्थितियों, संघर्षों और प्रयासों का पता लगाती है, जो भारत में सूचना का अधिकार को वास्तविकता का रूप देने जमीनी स्तर पर शामिल थे। यह इकाई उस प्रक्रिया को भी दर्शाती है, जो वर्तमान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधिनियमन के पीछे चली गई। यह भारत में औपचारिक रूप से सूचना का अधिकार को मान्यता दिलाने में लोगों के समूहों द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका पर विचार करती है।

10.2 नागरिक समाज का अर्थ, महत्व और भूमिका

नागरिक समाज स्वयं लोगों द्वारा संचालित समाज है। इसकी उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई है; हालांकि समय के साथ समझ और अर्थ बदल गए है। रोमन शब्द ''सोसाइटस सिविलिस'' (Societas Civil's) इसका मूल शब्द था, जिसका पर्याय एक अच्छा समाज था। वह जर्मन दार्शनिक हेगेल थे, जिन्होंने नागरिक समाज शब्द और इसका अर्थ अंकित किया जिसे हमें आज समझते हैं। एक नागरिक समाज में, लोग स्वेच्छा से समाज के कल्याण के वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने या राज्य के सामने लोगों की समस्याओं को उठाने के लिए साथ आते हैं। मूलरूप से, राज्य की रिक्तियों को नागरिक समाज द्वारा ठीक से भरा जा सकता है। नागरिक समाज शब्द का प्रयोग मूलरूप से समाज में लोकप्रिय आंदोलन का वर्णन करने के लिए किया गया था। समय बीतने के साथ यह रिक्त स्थान गैर राज्य हितधारकों जैसे गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ), स्वयं सहायता समूह, व्यावसायिक संघ, सामाजिक आंदोलन और विशेष हितों के समूह की विविधता को शामिल करने के लिए विस्तारित हो गया है। एंटोनियों ग्राम्सकी (Antonio Gramsci) कहते हैं, 'नागरिक समाज' शब्द 18वीं शताब्दी में उभरा है और 20वीं शताब्दी में एक स्व–विनियमित समाज, राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त और एक अलग और व्यवहार्य सत्ता मानते हुए पूरी तरह से नई अवधारणा के

साथ एक चर्चा का शब्द बन गया है। आज नागरिक समाज की धारणा को आमतौर पर गैर–सांख्यिकीय संस्थाओं के समूह के साथ पहचाना जाता है, जो बड़े पैमाने पर लोगों के हितों की सेवा के लिए खड़े होते हैं। नागरिक समाज को उन लोगों के योग के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो एक साथ आते है और अपने आप को सामान्य हितों के इर्द–गिर्द संगठित करते हैं।

नागरिक समाज में एक स्वायत्त स्थान होता है, जो राज्य और सरकार से स्वतंत्र होता है, जहाँ से नागरिक, राज्य पर नजर रखते हैं या राज्य से स्वतंत्र रूप से जो कुछ भी करना चाहते हैं वह करते हैं। नागरिक समाज को एक गैर दलीय राजनीतिक क्षेत्र के रूप में मान्यता दी जाती है, जहाँ व्यक्ति एक साथ आते हैं और स्वेच्छा से सार्वजनिक भलाई को बढ़ावा देने के लिए संघ बनाते है। नागरिक समाज स्व–संगठित संघ और सामाजिक आंदोलन को संदर्भित करता है, जो राजनीतिक संस्थानों में सत्ता के लिए पार्टियों और अन्य प्रत्याशी को शामिल करने वाले सत्ताधारकों को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं (या नहीं कर सकते हैं)। नागरिक समाज लोकतांत्रिक सरकार को अधिक प्रभावशाली बनाता है। राज्य में बदलाव के बिना, नागरिक समाज स्वयं लोकतंत्र नहीं ला सकता है। नागरिक समाज संगठनों को विकसित होने के लिए संरक्षित स्थान प्रदान करने और अपने मतभेदों पर बातचीत करने की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए राज्य निकासी के कुछ रूप होने चाहिए।

नागरिक समाज आज बहुत महत्वपूर्ण शब्द है और नागरिक समाज की अवधारणा को ध्यान में रखे बिना लोकतंत्र और मानवाधिकारों पर कोई भी चर्चा अधूरी है। एक लोकतंत्र को मजबूत नागरिक समाज की आवश्यकता होती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार के सभी अंग संविधान के मानकों के भीतर काम करते हैं। समाज के सर्वांगीण विकास के लिए नागरिक

समाज आवश्यक है। नागरिक समाज संगठन, सरकारी नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं और विश्वास और आपसी सम्मान के आधार पर समुदाय की भावना का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए नागरिक समाज, समाज को आकार देने और पुनःव्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नागरिक समाज भी लोगों और सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। ''वास्तविक व्यवहार में, जहाँ सरकार विफल हो जाती है, या राजनीतिक दल अवसर चूक जाते हैं, नागरिक समाज को वह स्थान भरना चाहिए, विशेष रूप से समाज के हाशिए पर रहने वाले और वंचित वर्ग की अपेक्षाओं पर लोगों को खरा उतरना चाहिए।'' (Kumar, 2011)

नागरिक समाज संगठन गैर राज्य, गैर–लाभकारी, स्वैच्छिक संस्थाएं है, जो सामाजिक क्षेत्र में लोगों द्वारा बनाई गई है, जो राज्य और बाजार से अलग हैं सीएसओ (नागरिक समाज संगठन) हितों और संबंधों की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे समुदाय आधारित लोगों के संगठनों के साथ–साथ गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को भी शामिल कर सकते हैं।

बोध प्रश्न 1

नोटः i) अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिये।

ii) अपने उत्तरों की जाँच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिये।

1) सुशासन में सूचना के अधिकार के महत्व की चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) नागरिक समाज को परिभाषित कीजिए तथा भारत में सूचना का अधिकार व्यवस्था लाने में नागरिक समाज और इसकी भूमिका की व्याख्या कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

10.3 भारत में नागरिक समाज आंदोलनों का इतिहास

भारतीय इतिहास में सबसे शक्तिशाली और चर्चित आंदोलन, जिनका नागरिकों द्वारा नेतृत्व किया गया, वह थे 1905 के 'स्वदेशी आंदोलन'। संभवतः भारतीय इतिहास में सबसे प्रसिद्ध आंदोलनों में से एक, सत्याग्रह हजारों लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से एक साथ लाया। अंग्रेजों को उनके देश वापस भेजने और भारत को विदेशी शासन से मुक्त करने के लिए महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए

गए अहिंसा आंदोलन को अंततः सफलता मिली। ''साइलेंट वैली प्रोटेस्ट'' (Silent Valley Protest) (केरल के पलक्कड़ जिले में एक सदाबहार उष्णकटिबंधीय जंगल), 1973 में कई कार्यकर्ताओं और लोगों को एक साथ लाया। विरोध एक जलविद्युत परियोजना से घाटी को बाढ़ से रोकने पर केंद्रित था। ''चिपको आंदोलन'' में लोगों ने पेड़ों को काटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। 1970 के दशक के आरंभ में विरोध शुरू हुआ। जब महिलाओं के एक समूह ने वृक्षों को काटने का विरोध किया और पर्यावरण को बचाने के लिए अपने हरित आंदोलन के समर्थन में पूरे भारत में हजारों लोगों को एक जुट किया।

1980 के दशक के जंगल बचाओ आंदोलन में, जब सरकार ने प्राकृतिक साल के जंगल को अत्यधिक मूल्यवान सागौन से बदलने का निर्णय लिया, तो बिहार के आदिवासी इस निर्णय का विरोध करने के लिए बड़ी संख्या में सामने आए। बिहार में शुरू होने के बाद, यह आंदोलन उड़ीसा और झारखंड के अन्य राज्यों में भी फैल गया। नर्मदा नदी के पास बड़ी संख्या में बन रहे बांधों के विरूद्ध 1985 का बहुत प्रसिद्ध नर्मदा बचाओं आंदोलन, बड़ी संख्या में आदिवासियों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को एक साथ लाया। कई प्रमुख हस्तियां और लोग कारण से अपना समर्थन दिखाने के लिए भूख हड़ताल पर चले गए। 1990 के दशक में मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS) के नेतृत्व में विभिन्न जन आंदोलनों के उदय ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधिनियमन की दिशा में एक ठोस प्रयास किया।

सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के नेतृत्व में 2011 के जन लोकपाल विधेयक के लिए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन ने बड़ी संख्या में लोगों को एक जुट किया, जिससे यह दशकों में अपनी तरह का एक अनूठा आयोजन बन गया। 2012 के

निर्भया आंदोलन ने भारत में हलचल मचा दी, जब राजधानी दिल्ली में सामूहिक बलात्कार की घटना के विरोध में हजारों लोगों ने एक याचिका पर हस्ताक्षर किए। इस जन आंदोलन ने सरकार को महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदमों की घोषणा करने के लिए मजबूर किया और 2013 में आपराधिक कानून सुधारों में कायापलट कर दी।

10.4 सूचना का अधिकार के उद्भव में नागरिक समाज आंदोलनों की भूमिका

नागरिक समाज की संस्था भारत के लिए अजनबी नहीं है। हमारे पास भारत में नागरिक समाज संगठन का एक लेखा इतिहास है। भारत में नागरिक समाज की जड़े प्राचीन और मध्यकाल से है। ''जाति पंचायत'', गांव ''पंचायत'' या ''व्यापार संघ'' सभी स्थानीय संस्थाओं के रूपों का वर्णन करते हैं। ये संस्थाएं राजनीतिक गतिशीलता के परिवर्तनों से अछूती रही और राज्य के नियंत्रण से स्वायत्त थी।[2] भारत की स्वतंत्रता के पश्चात्, लोग निराश थे क्योंकि सरकार लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकती थी। नागरिकों की अस्वस्थता के प्रति राज्य की गैर–जवाबदेही के परिणामस्वरूप देश में गैर–राज्य हितधारकों की संख्या में अल्प अवधि में तेजी से वृद्धि हुई सरकार के प्रति आम आदमी की बढ़ती निराशा के साथ और सरकार के कुलीन वर्चस्व वाले संस्थानों से अलग–थलग पड़े गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों के विविध हितों और अपेक्षाओं का जवाब देने में असमर्थ थे। परिणामस्वरूप, नागरिक समाज ने लोगों

[2]

की आकांक्षाओं और सरकार की संस्थाओं के बीच बनाए गए रिक्त स्थान में एक महत्वपूर्ण स्थान पर अधिकार स्थापित कर लिया।[3] (Mathur, 2005)

भारत में नागरिक समाज जनमत जुटाने और विभिन्न तरीकों से लोक नीतियों में बदलाव का सुझाव देने में सबसे आगे रहा है। लोक नीति की सफलता व्यापक रूप से नागरिक समाज की प्रभावशाली प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है। नागरिक समाज की भूमिका महत्वपूर्ण और उत्प्रेरक है क्योंकि यह लोगों को उनके संवैधानिक और अन्य वैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूक कर सकती है। भारत में कई नीतिगत पहल नागरिक समाज के कार्यों, स्थानीय प्रतिनिधियों, संगठनों, सरकारी विभागों और निजी निवेशकों की सक्रिय भागीदारी की भूमिका पर आधारित है। नागरिक समाजों की ओर से इस तरह की पहल के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम एक आधार प्रदान करता है। नागरिक समाज समूहों को लोगों के लिए सूचना गृह के रूप में कार्य करना होता है, जिससे उन्हें सरकार के डेटा तक पहुँचने और रहस्योद्घाटन करने में सहायता मिलती है। इसके महत्व को उजागर करने के लिए उन्हें सूचना तक पहुँच कर विश्लेषण करने की आवश्यकता है।[4] (Power to the people, 2005)

भारत में शासन में सुधार के साथ–साथ लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नागरिक समाज का सशक्तिकरण एक अनिवार्य आवश्यकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद देश ने अपने नागरिक समाज को सशक्त बनाने में बहुत प्रगति की है और यह अधिनियम सुशासन और लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तभों में से एक बन गया है। ''नागरिक समाज'' शब्द में वे सभी नागरिक शामिल हैं जो सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रयोग करते हैं,

3

4

सूचना का अधिकार कार्यकर्ता और गैर सरकारी संगठन जो नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए आगे आते हैं।

भारत में सूचना तक पहुँच की आवधारणा गोपनीयता से भी पुरानी है। भारत परंपरागत रूप से खुला समाज रहा है। लेकिन ब्रिटिश शासन ने यहां गोपनीयता की संस्कृति को स्थापित किया, जिसके कारण कार्यालयों में कर्मचारियों का उदासीन मनोभाव लोगों की सूचना की मांग के प्रति था। ''1923 का अधिकारिक गुप्त अधिनियम'', स्पष्ट रूप से अधिकांश सूचनाओं के प्रसार पर रोक लगाता है और अधिकांश लोक दस्तावेजों को नागरिकों की पहुँच से बाहर रखा जाता है। भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी अधिकारिक सूचनाओं पर नौकरशाही और सरकारी नियंत्रण की औपनिवेशिक विरासत जारी रही।

दिलचस्प बात यह है कि यद्यपि, भारत ने संवैधानिक जनादेश के अनुसार सरकार ने संसदीय स्वरूप को अपनाया, जिसका अप्रत्यक्ष रूप से उसके लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। लेकिन प्रतिनिधि लोकतंत्र के जन्म की अपेक्षा इसके बाद की विफलताओं ने नागरिक समाज संगठनों को पारदर्शिता शासन के लिए प्रयास करने के लिए जन्म दिया। लोगों में सहयोगी लोकतंत्र की ओर बढ़ने का आग्रह था ताकि देश के शासन में उनकी सुनवाई हो सके।

विभिन्न हितधारक सूचना प्राप्त करने के अधिकार के लिए संघर्ष का हिस्सा बने रहे, जो स्वाभाविक रूप से जनता का था लेकिन उनसे दूर रखा गया था। 1990 में, ग्रामीण गरीबों के बुनियादी आर्थिक अधिकार और सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुँच एक ज्वलंत प्रश्न और चिंता थी। अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, निखिल डे, अंची, शंकर सिंह, शैलेश गांधी, अरूणा रॉय और अन्य प्रभावशाली नेताओं के साथ कई आंदोलनों ने उनके लिए सूचना का अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया। पारदर्शिता की प्रासंगिकता और महत्व एक राष्ट्रीय

मंच पर तब सुर्खियों में आया जब राज्य स्तर पर सूचना के अधिकार के लिए छोटे, क्षेत्रीय आंदोलनों को सबसे आगे लाया गया, कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों को धोखा दिया जा रहा था और उनकी पूरी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया था। भुगतानकर्ता सरकारी अधिकारी थे, जिन्होंने दावा किया था कि श्रमिकों ने वास्तव में उनके मुकाबले कम दिनों के लिए काम किया है। वे इस दावे को चुनौती नहीं दे सकते थे क्योंकि उपस्थिति रजिस्टर तक पहुँच, जिसमें उन्होंने प्रत्येक दिन काम करने के लिए अपने अगूंठे के निशान लगाए थे, उन्हें ''गोपनीय सरकारी रिकॉर्ड'' होने के कारणवश वंचित कर दिया गया था।

सूचना चाहने वालों के एक अन्य समूह में भारत के संघर्ष इच्छुक क्षेत्रों में समाज के लाभ के लिए काम करने वाले कार्यकर्त्ता शामिल थे। उन्होंने शासन प्रणाली में पारदर्शिता और विभिन्न वंचित व्यक्तियों और समूहों के मानवाधिकारों के लिए लड़ने के लिए हाथ मिलाया। उनका मुख्य तर्क यह था कि दुष्ट अवरोध मानवाधिकारों के हनन आदि को रोकने के उनके प्रयासों को रोक दिया गया क्योंकि उन्हें प्रासंगिक जानकारी तक पहुँच से वंचित कर दिया गया था।

कुछ पर्यावरणविदों के समर्थक थे, जो पर्यावरण के तेजी से विनाश और गिरावट के बारे में चिंतित थे। उन्होंने किसी भी विकासात्मक उपायों और उसके पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में जानकारी के विवरण, तक पहुँच के महत्व के बारे में अपने दायरे का प्रचार किया।

1985 में भोपाल गैस त्रासदी के बाद पर्यावरणीय गैर सरकारी संगठनों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कई आवेदन दायर किए गए, जिसमें पर्यावरण खतरों से संबंधित जानकारी तक पहुँच की मांग की गई थी। पारदर्शिता की लड़ाई में महत्वपूर्ण अन्य विभिन्न पेशेवर थे, विशेष रूप से पत्रकार, वकील, शिक्षाविद और कुछ सेवानिवृत और सेवारत सिविल सेवक। (Stuti, http://www.legal

serviceindia.com/legal/article-323-evolution and development of the night to information act in India.html)

सूचना के मौलिक अधिकार की ओर बढ़ना

भारत में, हालांकि, सरकार में अधिक पारदर्शिता की मांग आजादी के बाद शुरूआती दशकों में शुरू हुई थी। ये मांगे बहुत तर्कयुक्त नहीं थी और विशिष्ट मुद्दों और घटनाओं से संबंधित थी। हालांकि, यह केवल 1975 में था कि सूचना के मौलिक अधिकार की स्पष्ट घोषणा **यूपी बनाम राज नारायण और अन्य ((1975)4 SCC 428)** में देखी गई थी, जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि ''हमारी तरह एक जिम्मेदार सरकार में जहाँ सभी जनता के एजेंटों को अपने आचरण के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, वहाँ कुछ रहस्य हो सकते हैं। इस देश के लोगों को प्रत्येक सार्वजनिक कृत्य, वह सब कुछ जानने का अधिकार है, जो उनके लोक पदाधिकारियों द्वारा लोक रूप से किया जाता है। वे प्रत्येक लोक लेन–देन का विवरण जानने के अधिकारी है।''

एक अधिकार के रूप में सूचना के विचार को **एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ** (AIR 1982 SC 149) में और प्रोत्साहन मिला जब सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार माना और निम्नलिखित अवलोकन कियाः

''खुली सरकार की अवधारण जानने के अधिकार से प्रत्यक्ष उद्‌गम है, जो कि अनुच्छेद 19(1) (ए) के तहत गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। इसलिए, सरकार के कामकाज के संबंध में सूचना का प्रकटीकरण नियम होना चाहिए और गोपनीयता एक अपवाद को तभी उचित ठहराया जा सकता है, जब जनहित की सबसे सख्त आवश्यकता की मांग हो। न्यायालय का दृष्टिकोण लोक हित की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जितना संभव हो

सके गोपनीयता के क्षेत्र को कम करने के लिए होना चाहिए, यह ध्यान में रखते हुए कि प्रकटीकरण भी लोक हित का एक महत्वपूर्ण पहलू है।''

इसके अतिरिक्त नागरिक स्वतंत्रता के लिए लोक संघ (PUCL) और अन्य बनाम भारत संघ में इस प्रश्न से निपटने के दौरान कि क्या अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में मतदाताओं के प्रासंगिक विवरण जानने का अधिकार शामिल है। उनके उम्मीदवार जैसे संपत्ति, योग्यता और अपराध में शामिल वे किसके लिए मतदान करने जा रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ''इस देश के आम लोगों को संसद में उनका प्रतिनिधित्व करने वाले उम्मीदवार का पूरा विवरण जानने का मूल प्राथमिक अधिकार होना चाहिए। लोकतंत्र में सूचना प्राप्त करने के अधिकार को सर्वत्र मान्यता प्राप्त है और यह लोकतंत्र की अवधारणा से प्रवाहित होने वाला अधिकार है।''

भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बार–बार मान्यता के बावजूद कि सूचना का अधिकार लोकतंत्र की अवधारणा से बहने वाला एक प्राकृतिक अधिकार है, सरकार द्वारा इस अधिकार को एक उपयुक्त कानून के माध्यम से संस्थागत बनान के लिए बहुत कम प्रयास किए गए थे। सूचना का अधिकार पर तभी ध्यान देना शुरू हुआ जब ग्रामीण भारत में लोगों के समूहां ने काम करना शुरू किया। जमीनी स्तर पर जुटाव, गठबंधन बनाने और मजबूत वकालत के माध्यम से, इसने सरकार पर सूचना का अधिकार कानून लाने का दबाव डाला।

(i) मजदूर किसान शक्ति संगठन की भूमिका 1990 के दशक में चार मानवाधिकार कार्यकर्ताओं निखिल डे, अंची, शंकर सिंह और अरूणा रॉय के नेतृत्व में **मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS)** के नेतृत्व में विभिन्न जन

आंदोलनों के उदय ने सूचना का अधिकार के संस्थागतकरण की दिशा में एक ठोस प्रयास किया।

मजदूर किसान शक्ति संगठन मजदूरों (MKSS) और किसानों के सशक्तिकरण के लिए एक संघ है। यह एक जन संगठन है, जो सूचना के अधिकार अधिनियम की मांग के लिए जाना जाता है, जो श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की मांग से उत्पन्न हुआ है। (Mahan, 2009) भारतीय सूचना का अधिकार आंदोलन की उत्पत्ति मध्य राजस्थान में स्थित एक छोटे से स्थान देवडूंगरी में हुई, जो शीघ्र ही उन लोगों के लिए एक मिलन स्थल बन गया, जो सामाजिक विसंगितयों के बारे में चिंतित थे और स्थानीय अभिजात वर्ग और अधिकारियों का सामना करना नहीं जानते थे। (Naib, 2012) 1990 के दशक के आरंभ से, MKSS ने राजस्थान राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में एक जमीनी स्तर पर आंदोलन शुरू किया था, जिसमें उन मजदूरों और छोटे किसानों की ओर से सरकारी जानकारी प्राप्त करने की मांग की गई थी, जिन्हें प्रायः राज्य विकास परियोजनाओं में उनके सही वेतन से वंचित किया जाता था या सरकारी सूखा राहत के साथ–साथ लोक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राशन की वस्तुओं के समान वितरण के तहत न्यायोचित लाभ से भी वंचित रखा जाता था। MKSS ने सूचना का अधिकार आंदोलन को बदल दिया ''सूचना तक मुफ्त पहुंच की मांग न्यूनतम मजदूरी के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण पहलू बन गई।'' (Naib, 2012) तब तक मुख्य रूप से कुछ कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों द्वारा आरंभ किया गया आंदोलन एक जन आंदोलन में परिवर्तित हो गया, जो न केवल राजस्थान राज्य में बल्कि देश के अधिकांश हिस्सों में फैल गया। यह मुख्य रूप से पारदर्शिता की मांग के इस तेजी से प्रसार के परिणामस्वरूप था, कि एक राष्ट्रीय सूचना का अधिकार कानून के निर्माण की आवश्यकता महसूस की जाने लगी।

सूचना का अधिकार के लिए अपने लंबे संघर्ष के दौरान, जिसे आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 के बहाने से अस्वीकार कर दिया गया था, MKSS ने जन सुनवाई की विधि को सूचना का अधिकार (RTI) के लिए अपनी मांग को आवाज देने के लिए एक उपयुक्त उपाय के रूप में पहचाना। जन सुनवाई में अधिकारियों से विस्तृत दस्तावेज प्राप्त किए गए, खर्च के अभिलेख (रिकॉर्ड) को गांव के लोगों को सुनाया गया जो इकट्ठा हुए थे। ये जनसुनवाई सरकार से स्वतंत्र रूप से आयोजित की गई थी। लेकिन सरकारी अधिकारियों को भी इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। सुनवाई के रूप में, लोगों को अपनी गवाही देने के लिए आमंत्रित किया जाता था जो प्रायः आधिकारिक अभिलेख (रिकॉर्ड) और लोगों के अनुभवों के बीच अंतर को प्रकट करता था। MKSS द्वारा प्रथम जनसुनवाई 4 दिसंबर 1994 को राजस्थान के पाली जिले के कोट किराना में आयोजित की गई थी। जिसमें सभी विकास निधियों में पारदर्शिता की मांग की गई थी, जिसका एक बड़ा भाग भ्रष्ट नौकरशाहों और सरकारी एजेंसियों द्वारा दुरूपयोग किया जा रहा था। MKSS के अभियान ने आधिकारिक अभिलेख (रिकॉर्ड) की पारदर्शिता, सरकारी खर्च की एक सामाजिक लेखा परीक्षा और उन लोगों के लिए एक निवारण तंत्र की मांग की, जिन्हें उनका बकाया नहीं दिया गया था। अभियान ने कार्यकर्ताओं, सिविल सेवकों और वकीलों सहित लोगों के एक विशाल व्यापक प्रतिनिधित्व की कल्पना को पकड़ लिया। (Reddy, 2006)

राजसमंद, पाली, अजमेर और भैरों जिले में कई जनसुवाई के माध्यम से, MKSS ने समस्त राजस्थान में प्रणालीगत भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने भी सूचना के अधिकार के अपने वचन को पूरा नहीं किया। इसलिए, 5 अप्रैल, 1996 को,

MKSS ने अजमेर राजस्थान के व्यावर शहर में हड़ताल (धरना) की घोषणा की। (Ray, 1996)

सूचना के अधिकार की मांग को लेकर MKSS का चालीस दिवसीय धरना (विरोध में बैठना) ऐतिहासिक हो गया। प्रदर्शनकारी ग्रामीण राजस्थान से ब्यावर शहर में आए। इस विरोध की नूतन बात, भोजन और आश्रय जैसी अपेक्षित बुनियादी आवश्यकताओं की अपेक्षा गरीबों द्वारा सूचना प्राप्त करने की मांग थी। धरने के दौरान ब्यावर में उपप्रभागीय पदाधिकारी को ज्ञापन देकर स्थानीय खर्च का अभिलेख (रिकॉर्ड) मांगा गया।

विरोध एक सौ पचास (150) से अधिक गांवों के समर्थन से शुरू हुआ। ब्यावर में इन गांवों और व्यक्तियों से अनाज के दान द्वारा इस का समर्थन किया गया था। विरोध को जारी रखने के लिए लगभग 46,000 रूपये का दान दिया गया। आसपास के सब्जी विक्रेताओं ने प्रदर्शनकारियों को भोजन और पानी उपलब्ध कराया। डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। स्थानीय लोग शामिल हुए और ग्रामीण प्रदर्शनकारियों के साथ चल दिए। ब्यावर के लोगों ने विरोध को गले लगा लिया और इसे अपना बनाना शुरू कर दिया। विरोध को गीत, रंगमंच और कठपुतली सहित सांस्कृति अभिव्यक्ति द्वारा चिहिनत किया गया था। स्थानीय सांस्कृतिक समूह शामिल हुए। इनमें भक्ति गायकों (भजन मंडली) का एक समूह शामिल था, जो प्रदर्शनकारियों की मांगों के समर्थन में भक्ति गीतों की पैरोडी (हास्यपूर्ण व्यंग काव्य) गाता था। बेगपाइपर और स्थानीय कवि भी शामिल हुए। श्रमिक संघ के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने भी अपना समर्थन दिया। (Mishra, 2003)

जैसे ही विरोध ने गति पकड़ी, राजस्थान के इस छोटे से शहर में हो रही असाधारण घटनाओं को देखने के लिए देशभर से लोगों ने ब्यावर का दौरा करना शुरू कर दिया। ब्यावर शहर में पत्रकार, कानूनविद और कलाकार, कई

अन्य लोग आए। आने वाले वरिष्ठ पत्रकारों में निखिल चक्रवर्ती, कुलदीप नैयर और प्रभाष जोशी शामिल थे। प्रभाष जोशी ने जनसत्ता अखबार में ''हम जानेंगे, हम जिएंगे'' शीर्षक से एक ऐतिहासिक संपादकीय लिखा। यह शीर्षक भारत में सूचना का अधिकार आंदोलन का नारा बन गया और लोकतंत्र में ''जानने का अधिकार जीने का अधिकार'' के नारे के साथ संप्रभु अधिकारों का दावा करने के लिए संशोधित किया गया था (Roy, *et.al*, 2010)। चालीस दिनों के बाद 16 मई, 1996 को धरना समाप्त हुआ, जब राजस्थान सरकार द्वारा श्री अरूण कुमार के नेतृत्व में स्थानीय प्रशासन के दस्तावेजों तक मुफ्त पहुंच से संबंधित लाभों और जोखिमों को देखने के लिए एक समिति नियुक्त की गई। समिति ने 30 अगस्त, 1996 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन इसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। इसलिए, अधिक जन सुनवाई और धरना का पालन किया गया। (Naib, 2012)

MKSS के नेतृत्व में 1996 का ब्यावर धरना, जहाँ अभियान की धारणा का जन्म हुआ, न जानने के अधिकार की आवश्यकता के लिए तीन मूलभूत सिद्धांतों को प्रकट किया। प्रथम, अपने लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही के साथ–साथ खातों और अभिलेखों की पारदर्शिता का अधिकार था। नारा ''हमारा पैसा, हमारे खाते; हमारा पैसा, हमारा हिसाब'' ने सूचना का अधिकार की आवश्यकता को संक्षेप में प्रस्तुत किया। दूसरी मान्यता थी कि सार्वजनिक वाद–विवाद के पश्चात् लोगों द्वारा अधिकार के लिए कानूनी अधिकार का मसौदा तैयार किया जाना चाहिए, उसका निर्माण करना चाहिए और लोगों का उस पर स्वामित्व होना चाहिए। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण एक निर्वाचित राजनीतिक सरकार की जनता के प्रति लोकतांत्रिक जवाबदेही थी (Roy, 2019)। ब्यावर से शुरू हुए इस आंदोलन को पूरे देश के लोगों से एकजुटता और समर्थन मिला।

ब्यावर धरने ने सूचना का अधिकार अभियान को राष्ट्रीय मानचित्र पर पहुँचा दिया। इसने एक मजबूत सूचना का अधिकार कानून की राष्ट्रव्यापी मांग की नींव भी रखी। अक्टूबर 1995 में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA), मसूरी में आयोजित एक बैठक में सूचना का अधिकार कानून की आवश्यकता पर चर्चा हुई थी। इस बैठक में, कार्यकर्ताओं, पेशेवरों और प्रशासकों ने समान रूप से भाग लिया, एक उपयुक्त राष्ट्रीय निकाय की स्थापना की कार्यसूची को आगे बढ़ाया।

(ii) सूचना के अधिकार के लिए राष्ट्रीय अभियान की भूमिका

अगस्त, 1996 में, नई दिल्ली में गांधी शांति संस्थान में उचित रूप से बैठक बुलाई गई थी, जहाँ लोगों के सूचना के अधिकार के लिए राष्ट्रीय अभियान एन. सी.पी.आर.आई. (National Campaign for People's Right to Information-NCPRI) का जन्म हुआ था। इसके संस्थापन सदस्यों में सामाजिक कार्यकर्ता, वरिष्ठ पत्रकार, वकील, पेशेवर, सेवानिवृत प्रतिष्ठित सिविल सेवक और शिक्षाविद शामिल थे और इसका एक प्राथमिक उद्देश्य सूचना के मौलिक अधिकार के प्रयोग को सुविधाजनक बनाने वाले राष्ट्रीय कानून के लिए अभियान चलाना था। MKSS के साथ, अन्य संगठन जिन्होंने इस अभियान में सक्रिय रूचि ली, वे थे– आंध्र प्रदेश में लोक सत्ता, दिल्ली में परिवर्तन और भारतीय प्रेस परिषद। NCPRI ने भी अधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 को हटाने की उत्साह सहित वकालत की।

सफलता सुनिश्चित करने के लिए एन सी पी आर आई ने मिश्रित कार्यनीति अपनाई। जबकि सूचना के अधिकार के लिए राष्ट्रीय अभियान ने राज्य के भीतर सहयोगियों को विकसित किया, इसने अपनी शक्ति सतर्क और संगठित नागरिकों के निरंतर हो रहे जनता के दबाव से भी प्राप्त की। इसमें लोक

सुनवाई या जन सुनवाई शामिल थी, जिसमें अधिकारिक अभिलेख (रिकॉर्ड) की तुलना ग्राम समितियों या पंचायतों द्वारा प्रदान की जाने वाली वास्तविक सेवाओं के साथ–साथ राज्य और राष्ट्रीय स्तर की बैठकों और कार्यकर्ताओं के सम्मेलनों से की जाती थी। एन सी पी आर आई ने सूचना का अधिकार संदेश के साथ कार्यकर्ताओं, सामान्य ग्रामीणों और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले छात्रों के कारवां को शामिल करते हुए यात्रा या यात्राएं भी आयोजित की, जिन्हें गीतों और रेखाचित्रों के माध्यम से संप्रेषित किया गया। आंदोलन ने हिंदी और अंग्रेजी में समाचारपत्र भी छापे और मीडिया का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि, एन सी पी आर आई नेतृत्व ने पारदर्शिता और जवाबदेही पर अंतर्राष्ट्रीय नव–उदारवादी एजेंडे से स्वयं को दूर करने की कोशिश की, लेकिन इसका अप्रत्यक्ष रूप से लाभ भी हुआ। आर्थिक उदारीकरण की प्रचलित विचारधारा ने, राज्य के हस्तक्षेप के अपने आलोचनात्मक दृष्टिकोण के साथ, कुछ सरकारी अधिकारियों के बीच सेवा–वितरण और शासन की विफलता और अधिक जवाबदेही की आवश्यकता के बारे में अधिक खुलेपन को प्रेरित किया।

1997 में राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर सूचना का अधिकार के लिए अभियान तेज हो गया। एन सी पी आर आई सूचना तक पहुँचने के संघर्ष के लिए एक व्यापक आधारित मंच बन गया और इसने राजस्थान सरकार को सूचना के अधिकार पर एक कानून पारित करने के लिए विवश किया। राजस्थान सरकार ने सूचना के अधिकार के महत्व को अनुभव किया और 1 मई, 2000 को सूचना का अधिकार कानून पारित किया, जो जून 2000 से प्रभावी हुआ। राजस्थान में अधिनियम ने नागरिकों को किसी भी क्षेत्र में शासन की जानकारी प्राप्त करने का कानूनी अधिकार दिया।

एन सी पी आर आई ने सूचना के अधिकार पर एक राष्ट्रीय कानून के लिए उद्देश्य तैयार करने का कार्य लिया और इस उद्देश्य के लिए एक सूचना का अधिकार अधिनियम का मसौदा तैयार किया। एक बार मसौदा तैयार होने के बाद, यह मसौदा विधेयक भारतीय प्रेस परिषद् (Press council of India- PCI) को भेजा गया था, जिसकी अध्यक्षता एक सहानुभूति अध्यक्ष, न्यायमूर्ति एस.बी. सावंत ने की जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश थे। प्रेस परिषद ने मसौदा विधेयक की जाँच की और कुछ परिवर्धन और संशोधनों का सुझाव दिया। संशोधित विधेयक तब दिल्ली में आयोजित एक बड़ सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें इसके प्रतिभागियों में भारत के अधिकांश महत्वपूर्ण राजनीति दलों के प्रतिनिधि शामिल थे।

(iii) भ्रष्टाचार के विरूद्ध अन्ना हजारे का संघर्ष

एक सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे जिन्होंने भारत के नागरिकों के पक्ष में कई नागरिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और संघर्ष किया तथा भ्रष्टाचार के विरूद्ध भी कदम उठाया। उन्होंने 11 मार्च, 1995 को सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार के विरूद्ध अपना संघर्ष शुरू किया। 6 अप्रैल, 1995 को उन्होंने भारत में सूचना के अधिकार कानून के लिए अपना आंदोलन शुरू करने के लिए आजाद मैदान, मुंबई का चयन किया। उन्होंने 12 जनवरी, 1998 को सरकार को एक ज्ञापन दिया, जिसमें भारतीय समाज से भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सूचना के अधिकार की मांग की गई थी। उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम तैयार करने में ढिलाई बरतने के लिए महाराष्ट्र में कांग्रेस–एनसीपी सरकार की आलोचना की। 2001 में फिर से, उन्होंने सूचना के अधिकार की अपनी मांग को आगे बढ़ाने के लिए अपने समर्थकों के साथ मौन आंदोलन आरंभ किया। उन्होंने सूचना के अधिकार की वकालत करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न

अधिकारियों को कई पत्र लिखे। अंत में, उन्होंने 9 अगस्त, 2003 को मुंबई के आजाद मैदान में अनशन किया, जिसके कारण सूचना के अधिकार के लिए जन आंदोलन हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने दबाव में घुटने टेककर सुशासन सुनिश्चित करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2002 लागू किया गया।

अन्ना हजारे के आंदोलन ने शीघ्र ही अरूणा रॉय, अरविंद केजरीवाल, शैलेश गांधी, प्रकाश कर्दले जैसे अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ भारत में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए एक कानून की मांग के साथ सूचना का अधिकार पर केंद्रीय कानून के लिए सामर्थ्य एकत्रित किया। अन्ना हजारे के नेतृत्व में 2011 के जनलोकपाल विधेयक के लिए ऐतिहासिक अखिल भारतीय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन ने भी भ्रष्टाचार के विरूद्ध लड़ाई को मजबूत किया और सूचना के मौलिक अधिकार की गारंटी देने वाले अखिल भारतीय कानून की मांग की।

(iv) सूचना का अधिकार के लिए राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल अभियान

1987 में, कई राष्ट्रमंडल पेशेवर संघों ने राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल (Commonwealth Human Right Introduce- CHRI) की स्थापना की। यह एक स्वतंत्र, गैर–पक्षपातपूर्ण, अंतर्राष्ट्रीय गैर–सरकारी संगठन है, जिसे राष्ट्रमंडल के देशों में मानवाधिकारों की व्यावहारिक प्राप्ति सुनिश्चित करने का अधिकार प्राप्त है। सी.एच.आर.आई का मत है, कि सूचना का अधिकार विभिन्न मानवाधिकारों के बीच एक मौलिक कड़ी प्रदान करता है और इसलिए सभी राष्ट्रमंडल देशों में इसके परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा देने की वकालत करता है। 1997 के मध्य में, जब जमीनी स्तर पर और सूचना का अधिकार के लिए विधायी मोर्चे पर महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो रहे थे, तो सी.एच.आर.आई ने भी इस मुद्दे पर एक देशव्यापी चर्चा शुरू की। यह मुद्दों को सरल बनाकर उनकी सहायता करने के लिए विभिन्न

स्तरों पर जनता को लक्षित करने वाले प्रकाशनों की एक श्रृंखला के साथ सामने आया।

सी.एच.आर.आई द्वारा एक साथ लाए गए नागरिक समाज समूहों ने लोगों को अधिकार के संचालन के बारे में शिक्षित करने और सूचना के लिए आवेदन दाखिल करके सरकारी आदेशों को सक्रिय करने के लिए एक अभियान शुरू किया।'' सी.एच.आर.आई ने कई कार्यशालाएं और अन्य छोटी बैठकें भी आयोजित की, जो अधिकतर क्षेत्रीय स्तर पर थी, लेकिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आयोजित की गई। प्रतिभागी विभिन्न पृष्ठभूमि से थे, इसमें गैर सरकारी संगठनों (एन जी ओ) के प्रतिनिधि, शिक्षाविद वकील और न्यायविद, युवा समूह और छात्र, मीडिया कार्यकर्ता, नौकरशाह और जीवन के अन्य क्षेत्रों के लोग शामिल थे। कार्यशालाओं को लोगों की सूचना आवश्यकताओं, सूचना तक पहुँच की समस्याओं और संभावित कानून से लोगों की अपेक्षा पर प्रतिक्रिया देने के लिए डिजाइन किया गया था। कार्यशाला में कुछ व्यावहारिक मुद्दों पर भी चर्चा की गई।

सी.एच.आर.आई सूचना का अधिकार कानून बनाने के लिए केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर पहलों में भी शामिल रहा है। इसने सूचना का अधिकार को संस्थागत बनाने के उनके प्रयासों में विशेष रूप से मध्य प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक और राजस्थान राज्यों में सक्रिय भूमिका निभाई। सी.एच.आर.आई अभियान सूचना का अधिकार को आगे बढ़ाने में काम करने वाले सभी पणधारियों को एक साथ लाया। इसने विभिन्न स्तरों पर काम करने वाले विभिन्न हितधारकों को एकजुट किया। इसने दोनों नागरिक समाज के भीतर और साथ ही सरकार के साथ भी काम करने वाले हितधारकों को भी एकजुट किया। सी.एच.आर.आई ने सूचना का अधिकार विधेयक में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों का सुझाव देकर सूचना का

अधिकार अधिनियम के अधिनियमन में एक प्रमुख भूमिका निभाई, जिसे एन.सी.पी. आर.आई. ने संसद के समक्ष रखा था।

(v) उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केंद्र और अन्य छोटे समूहों का अभियान

भारत में उपभोक्ता अधिकार संरक्षण आंदोलन भी उपभोक्ता अधिकारों को प्रभावित करने वाले मामलों के संबंध में पारदर्शिता की कमी से चिंतित रहा है। माल में खराबी और सेवाओं में कमी के कारण निर्माताओं और विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं को ठगा जा रहा था, क्योंकि उनके पास खरीदे गए सामानों की उचित जांच या अनुबंधों के मानक रूपों के कारण सेवाओं के बारे में जानकारी का कोई अधिकार नहीं था, जहां नियम और शर्ते पूर्व निर्धारित होते है। भारत का उपभोक्ता निरीक्षण समाज, उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केंद्र, ग्राहक पंचायत और अन्य उपभोक्ता अधिकार आंदोलन में शामिल थे। उनकी एक मांग उपभोक्ता मामलों में सूचना के अधिकार की थी। उन्होंने एक सूचना तक पहुँच विधेयक 1996 भी तैयार किया था। 1980 के दशक के आरंभ में, अहमदाबाद ने विश्व के अन्य भागों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में सूचना कानूनों की स्वतंत्रता पर शोध किया। उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केंद्र ने अपने शोध के आधार पर कानून का मसौदा तैयार किया, जिसे एक निजी सदस्य के विधेयक के रूप में संसद में प्रस्तुत किया गया। उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केंद्र ने उपभोक्ता शिक्षा को जन–जन तक पहुँचाने के लिए उपभोक्ता कल्याण और उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दे पर कई कार्यशालाओं का भी आयोजन किया।

अन्य छोटे समूहों और आंदोलन जो अन्य विभिन्न कारणों के लिए संघर्ष कर रहे थे, ने भी अपनी वकालत में सूचना के अधिकार का आहवान किया था। 'पंचायत बचाओ अभियान', बिहार और झारखंड में एक अनौपचारिक आंदोलन, स्थानीय

चुनाव कराना चाहता था, जिससे राजनीतिक प्रतिनिधित्व और नागरिकों के अधिकारों के महत्व के बीच संबंध बन गया। वे अपने मतदाता शिक्षा कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में सूचना के अधिकार कानून की मांग कर रहे थे।

कुछ गैर–सरकारी संगठनों ने अपने स्वयं के अभिलेख (Record) खोलकर अपने संगठनों में ''पारदर्शिता मेले'' आयोजित करके सूचना के अधिकार की मांग को मजबूत किया है। यह एक अनूठी महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी क्योंकि पारदर्शिता की मांगों के प्रति सरकारों की प्रथम प्रतिक्रिया प्रायः गैर सरकारी संगठनों, विशेष रूप से विदेशी खोज प्राप्त करने वालों पर, अखंडता और खुलेपन की कमी का आरोप लगाने के लिए होती है। गोवा में, सूचना के अधिकार के मुद्दों को पत्रकारों द्वारा उठाया गया, बाद में नागरिक समाज समूहों द्वारा समर्थित किया गया। मीडिया ने भी सूचना का अधिकार आंदोलन को लगातार सम्मिलित करके सूचना के अधिकार के आंदोलन का समर्थन किया। सूचना का अधिकार मुद्दे पर राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल अभियान के दौरान, रेडियो और टेलीविजन सहित राज्य और स्थानीय स्तर के मीडिया दोनों पर, इन स्थानीय चिंताओं से संबंधित मुद्दे को निरंतर अन्तर्निहित किया गया था।

बोध प्रश्न 2

नोटः i) अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिये।

ii) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) भारत में सूचना के अधिकार को विकसित करने में मजदूर किसान शक्ति संगठन, सूचना के अधिकार के लिए राष्ट्रीय अभियान और अन्य नागरिक समाज संगठनों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) जनसुनवाई से आप क्या समझते हैं? सूचना के अधिकार के आंदोलन में जनसुनवाई की भूमिका की चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

10.5 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधिनियमन में सरकार की पहलें

सूचना का अधिकार पर पहला प्रमुख मसौदा कानून भारत के प्रेस काउंसिल द्वार बनाया गया था। प्रेस कांउंसिल के मसौदे ने अपनी प्रस्तावना में पुष्टि की, कि

सूचना का अधिकार पहले से ही संविधान के तहत स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार के पहलू के रूप में संरक्षित है, जो कई बेहतर न्यायालयों के फैसलों के अनुरूप है। मसौदे ने प्रत्येक नागरिक के किसी भी लोक निकाय से सूचना प्राप्त करने के अधिकार की पुष्टि की। महत्वपूर्ण रूप से, सार्वजनिक निकाय शब्द में न केवल राज्य जैसा कि संविधान में परिभाषित हैं, बल्कि सभी निजी स्वामित्व वाले उपक्रम, गैर–सांविधिक प्राधिकरण, कंपनियां और अन्य गैर–सरकारी निकाय भी शामिल हैं, जिनकी गतिविधियां लोक हित को प्रभावित करती हैं।

इस प्रकार वाणिज्यिक क्षेत्र और गैर–सरकारी दोनों संगठनों को इस मसोदे की सीमा में शामिल किया गया था। मसौदे में सूचना के अधिकार पर सीमित संख्या में प्रतिबंधों का प्रावधान था, जो अन्य मौलिक अधिकारों के संबंध में अनुमत प्रतिबंधों के अनुरूप था, इनमें शामिल हैं, जहाँ प्रकटीकरण भारत की संप्रभुता और अखंडता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा, राज्य की सुरक्षा और विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, किसी अपराध की जांच, या जहां प्रकटीकरण से अपराध को बढ़ावा मिलेगा। व्यक्तिगत गोपनीयता और व्यापार और वाणिज्यिक हितों के प्रमाणिक आधारों को भी अपवाद के रूप में शामिल किया गया था। मसौदे में जानकारी प्रदान करने में विफल रहने के लिए व्यक्तिगत जुर्माना और अनुरोधित जानकारी की आपूर्ति में विफलता या इनकार के विरूद्ध स्थानीय नागरिक न्यायपालिका से अपील करने का भी प्रावधान है। (Naib, 2012)

एन.सी.पी.आर.आई ने तब इस बहुचर्चिच और व्यापक रूप से समर्थित विधेयक को भारत सरकार को इस अनुरोध के साथ भेजा कि सरकार इसे तत्काल कानून में बदलने पर विचार करे। उत्तर में, भारत सरकार ने उपभोक्ता कार्यकर्ता

स्वर्गीय श्री एच.डी. शौरी के अंतर्गत कार्य समूह तैयार किया। शौरी समिति को सूचना का अधिकार विधेयक के मसौदे की जांच करने और सिफारिशें करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिससे सरकार को पारदर्शिता को संस्थागत बनाने में सहायता मिलती। समिति ने शीघ्रता से कार्य किया और अपनी रिपोर्ट सरकार को स्थापित होने के कुछ महीनों के भीतर प्रस्तुत की तथा सूचना का अधिकार अधिनियम का अपना मसौदा तैयार किया। (Jain, 2006)

व्यापक विचार–विमर्श के बाद यह मसौदा भारत सरकार को भेजा गया था। यह 1996 में पहली बार एन.सी.पी.आर.आई और अन्य द्वारा तैयार किए गए विधेयक का एक बहुत ही पतला संस्करण था। इसलिए, अनिवार्य रूप से, शौरी समिति की सिफारिशों के आधार पर मसौदा विधेयक, संसदीय स्थायी समति को भेजा गया था, जिसने 2002 के पश्चात् अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं।

राष्ट्रीय सूचना स्वतंत्रता विधेयक, 2000 को 2002 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। विधेयक कई मायनों में अपूर्ण था, जिसमें इसका सीमित दायरा था जैसे (विशेष रूप से कवरेज से निजी निकायों का बहिष्कार), इसकी छूट का विस्तार, असफलता, जिसमें जनहित को कुचल देने की छूट, एक प्रभावशाली स्वतंत्र अपील तंत्र की अनुपस्थिति और लोक शिक्षा और निगरानी प्रावधानों को शामिल करने में विफलता (CHRI, 2004)। यदि अधिनियम को प्रभावशाली ढंग से अपने उद्देश्य की पूर्ति करनी थी तो इन कमियों को प्राथमिकता के रूप में ठीक किया जाना था।

इस तथ्य के बावजूद कि विधेयक के प्रावधान कई मायनों में कमजोर थे, इसे दिसम्बर, 2002 में पारित किया गया। विधेयक को सूचना की स्वतंत्रता (FOI) अधिनियम 2002 के अधिनियमन के रूप में जनरवरी 2003 में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। अधिनियम में प्रावधान था कि यह अधिसूचित तिथि से

प्रभावशाली होगा। दिलचस्प बात यह है, कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के बावजूद, इस अधिनियम को कभी अधिसूचित नहीं किया गया था और इसलिए कभी प्रभावशाली नहीं हुआ।

एन सी पी आर आई का द्वितीय सम्मेलन 2004 में दिल्ली में आयोजित किया गया था और इसमें फिर से देशभर से 1000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कार्य और शासन के विभिन्न क्षेत्रों में सूचना का अधिकार के उपयोग पर चर्चा करने के लिए सम्मेलन के एक भाग के रूप में तीस से अधिक कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। एन सी पी आर आई ने 2002 में नर्मदा नदी पर प्रस्तावित महेश्वर बांध के आसपास भोपाल में एक जन सुनवाई भी आयोजित की। इस जन सुनवाई में मुख्य रूप से परियोजना से प्रभावित लोगों में से तीन से चार सौ लोगों ने भाग लिया। परियोजना का निर्माण करने वाली कंपनी एस कुमार के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

नए राजनीतिक अवसरों ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के पारित होने की सुविधा प्रदान की। 2004 में राष्ट्रीय चुनावों की घोषणा की गई और सूचना का अधिकार अधिनियम को ''मजबूत बनाने'' का कांग्रेस पार्टी का घोषणापत्र में शामिल किया गया। मई 2004 में कांग्रेस पार्टी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यू पी ए) गठबंधन सरकार के एक हिस्से के रूप में सत्ता में आई और यूपीए ने एक ''न्यूनतम सामान्य कार्यक्रम'' तैयार किया, जिसने फिर से सूचना का अधिकार पर जोर दिया। जून 2004 में सरकार ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम के कार्यान्वयन को देखने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी के अधीन एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एन ए सी) का गठन किया। परिषद ने एफ.ओ.आई. (FOI) अधिनियम में शामिल किए जाने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों का सुझाव दिया। हालांकि यूपीए सरकार ने एफओआई (FOI) अधिनियम, 2002 को भंग करने और

नया कानून बनाने का निर्णय लिया। अगस्त 2004 में एन सी पी आर आई ने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद को सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 में सुझाए गए संशोधनों का एक संग्रह भेजा। 2002 अधिनियम को मजबूत और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए डिजाइन किए गए इस संशोधन पारदर्शिता पर काम कर रहे नागरिक समाज समूहों के साथ व्यापक चर्चा पर आधारित थे और अन्य संबंधित मुद्दों और यूपीए सरकार द्वारा अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में दिए गए उपक्रम के जवाब में थे कि सूचना का अधिकार अधिनियम को और अधिक प्रगतिशील, भागीदारीपूर्ण और सार्थक बनाया जाएगा।

उच्चतम न्यायालय ने एन सी पी आर आई की ओर से प्रशांत भूषण द्वारा दायर एक जनहित याचिका मामले (Centre For P.I.L & ORS vs UOI & ARR W.P. (C) 637/1998) में भी सूचना के अधिकार पर अधिसूचना जारी करने के लिए केंद्र सरकार के लिए 15 सितम्बर, 2004 की समय सीमा तय की थी।

एनएसी ने सुझाए गए अधिकांश संशोधनों का समर्थन किया और उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए भारत के प्रधानमंत्री से सिफारिश की। दिसम्बर 2004 में संसद के शीतकालीन सत्र में सूचना का अधिकार विधेयक पेश किया गया था। हालांकि, संसद में पेश किए गए इस विधेयक में कई कमजोरियां थी। एन सी पी आर आई के सुझाव के विपरीत, यह पूरे देश पर लागू नहीं हुआ बल्कि केवल केंद्र सरकार पर लागू हुआ। एन सी पी आर आई सहित नागरिक समाज समूहों के परिणामी आक्रोश ने सरकार को परिवर्तनों की समीक्षा करने के लिए मजबूर किया। विधेयक को तुरंत स्थायी समिति को भेजा गया और मंत्रियों के एक समूह को इसकी जांच करने और उस पर सिफारिशें करने के लिए कहा गया। स्थायी समिति की अंतिम रिपोर्ट मार्च, 2005 में लोकसभा में पेश की गई थी। अंततः संसदीय समिति और मंत्रियों के समूह की सिफारिशों को समायोजित

करने के लिए सरकार द्वारा पेश किए गए सौ से अधिक संशोधनों के बाद विधेयक पारित किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कि विधेयक का अधिकार क्षेत्र पूरे भारत को सम्मिलित करने के लिए बढ़ाया गया था। सूचना का अधिकार विधेयक, 2005 लोकसभा द्वारा 11 मई, 2005 को और राज्य सभा द्वारा 12 मई, 2005 को पारित किया गया था और इसे 15 जून, 2005 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। यह सूचना के अधिकार के रूप में कानून की किताब में अधिनियम, 2005 (2005 का 22) के रूप में आया था। पूर्ण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 इसके लागू होने के 120 दिनों के भीतर अर्थात् 12 अक्टूबर, 2005 को लागू हुआ। तब से, प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार से लड़ने और भारत सुशासन लाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम का उपयोग किया गया है।

बोध प्रश्न 3

नोटः i) अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिये।

ii) अपने उत्तरों की जाँच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिये।

1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधिनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली परिस्थितियों की चर्चा कीजिये।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

10.6 मूल्यांकन

2005 में भारत के सूचना का अधिकार अधिनियम का निर्माण व्यापक रूप से एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के रूप में दर्ज किया गया है। प्रस्तुत इकाई इस बात का विश्लेषण करती है, कि किस प्रकार विभिन्न पणधारियों के हित लोकतांत्रिक रूप से कानून के निर्माण में परिवर्तित हुए। सूचना का अधिकार अधिनियमन के लिए नागरिक समाज आंदोलन बहुहितधारकों को शामिल करते हुए परामर्शी और सहयोगी कानून बनाने की प्रक्रियाओं का एक उदाहरण है। सूचना के अधिकार के लिए वास्तविक आंदोलन जमीनी स्तर से शुरू हुआ। सूचना के अधिकार की मांग उसी तरह की गई थी, जैसे काम के अन्य अधिकार या न्यूनतम मजदूरी के अधिकार की मांग आम जनता द्वारा अपने जीवन के निर्वाह के लिए की जाती थी। मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS) द्वारा शुरू किया गया आंदोलन अन्य लोगों के आंदोलन एन सी पी आर आई, भ्रष्टाचार के विरूद्ध अन्ना हजारे के आंदोलन और सूचना के अधिकार के लिए उपभोक्ता संगठनों के संघर्ष से और मजबूत हुआ। आंदोलन को इसके वांछित परिणाम की ओर ले जाने के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल द्वारा भी समर्थन दिया गया था। नागरिक समाज संगठन सूचना का अधिकार अधिनियम के लिए लड़ाई इस तथ्य को भी प्रतिबिंबित करती हैं, कि जब परामर्श उन लोगों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हैं जो प्रस्तावित कानून से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना रखते हैं और यदि उनकी प्रतिक्रिा को शामिल किया जाता है, तो यह नीति और कानून बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण हो जाता है।

10.7 निष्कर्ष

12 अक्टूबर, 2005 को अधिनियमित भारत का पारदर्शिता कानून सूचना का अधिकार, लागू होने वाले सबसे शक्तिशाली कानूनों में से एक है। इसकी मान्यता में एक लंबा इतिहास शामिल है, लेकिन 1990 के दशक में ही कानून की मांग का संघर्ष वास्तव में शुरू हुआ था। राजस्थान में दैनिक मजदूरी के आधार पर काम करने वाले कुछ मजदूर अपने न्यूनतम वेतन से वंचित रह जाते थे। और साथ ही, उनकी सहायता के लिए एक गैर–राजनीतिक संगठन मजदूर किसान शक्ति संगठन आगे आया। MKSS के माध्यम से राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर जागरूकता पैदा करने के लिए कई जन सुनवाई आयोजित की गई। पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए एक कानून की मांग करते हुए, देश के अन्य हिस्सों के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इस आंदोलन में भाग लिया। 2005 में केंद्रीय कानून के लागू होने से पहले भारत के कई राज्यों ने अपने स्वयं के सूचना का अधिकार अधिनियम बनाए हैं।

हालांकि आंदोलन जमीनी स्तर पर शुरू हुआ, लेकिन इसका प्रभाव देश के सभी भागों से अनुभव किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर सूचना का अधिकार पर वकालत करने के लिए एन सी पी आर आई एक सहायता समूह के रूप में शामिल हुआ। सी एच आर आई ओर सी ई आर सी भी भारत में सूचना का अधिकार कानून के लिए लड़ाई में शामिल हुए, एन सी पी आर आई ने 1996 में एक मसौदा तैयार किया और इसे भारतीय प्रेस परिषद के समर्थन से सरकार को भेजा। सरकार ने मसौदा विधेयक श्री एच.डी. शौरी समिति को सौंप दिया। चूंकि सूचना का अधिकार कार्यकर्ता शौरी समिति की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए इसे संसदीय स्थायी समिति के पास भेज दिया गया था। अंततः सूचना की स्वतंत्रता

अधिनियम, 2000 पारित किया गया, लेकिन इसे कभी अधिसूचित नहीं किया जा सका।

2004 में जब यूपीए सरकार सत्ता में आई, तो वह एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम लेकर आई, जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम बनाने का वादा भी शामिल था। इस दुर्लभ अवसर का उपयोग एन सी पी आर आई द्वारा एक मजबूत कानून प्राप्त करने के लिए किया गया, जिसने लोगों की सूचना तक पहुँच को अधिकार के रूप में मान्यता दी। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कि वास्तविक पणधारियों के साथ नागरिक समाज संगठनों द्वारा अपनाया गया परामर्शी दृष्टिकोण अंततः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सफल अधिनियमन में पराकष्ठा पर पहुँच गया।

10.8 शब्दावली

जन सुनवाई *(Jan Sunwai)* : ''जन सुनवाई'' एक हिंदी मुहावरा है, को संदर्भित करता है, जिसका अर्थ है जनता की बातों की सुनना। यह स्थानीय लोगों से बनी एक अनौपचारिक अदालत की तरह है क्योंकि इससे न्यायाधीश जवाबदेही चाहते हैं, इसमें दंड देने की कोई प्रणाली शामिल नहीं है। जन सुनवाई स्थानीय लोगों को सरकारी नीतियों और लोक प्राधिकरणों की गतिविधियों से परिचित कराने का एक लोकतांत्रिक तरीका है। ताकि वे समझ सकें कि सरकार उनके समुदायों के विकास के लिए क्या कर रही है।

एन सी पी आर आई : नागरिकों को सूचना के अधिकार के लिए राष्ट्रीय अभियान (National Campain for People's Right's

to Information- NCPRI) की स्थापना 1996 में की गई थी। एन सी पी आर आई ने सबसे पहले सूचना का अधिकार पर कानून का मसौदा तैयार किया था। यह संगठनों और व्यक्तियों का एक नेटवर्क है, जो सरकारी अधिकारियों से पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करने के लिए सूचना का अधिकार कानून का उपयोग करता है, लेकिन जवाबदेही की मांग के लिए विभिन्न अन्य क्षेत्रों में सूचना का अधिकार के उपयोग का भी समर्थन करता है।

एन.ए.सी. (National Advsory Council- NAC) : भारत का राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (NAC) भारत के प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए प्रथम संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार द्वारा स्थापित एक निकाय था। एनएसी (NAC) एक 14 सदस्यीय समिति जिसमें पूर्व नौकरशाह, नागरिक समाज के सदस्य, शिक्षाविद और वकील शामिल थे। भारत के प्रधानमंत्री ने कैबिनेट मंत्रियों के परामर्श से सदस्यों की नियुक्ति की। उनकी भूमिका कानून का मसौदा तैयार करने में सहायता प्रदान करना था। NAC ने सूचना का अधिकार अधिनियम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

10.9 संदर्भ लेख

Biju, M.R. (2009). *Dynamics of Modern Democracy the Indian Experiences*. New Delhi, India: Kanishka Publishers.

CHRI. (2004). Detailed Analysis of the Indian Freedom of Information Act 2002 & Recommendations for Amendments. Retrieved from https://www.humanrightsinitiative.org/programs/ai/rti/news/india_foi_act_analysis_for_mps.pdf

Elliott, C.M. (2003). *Civil Society and Democracy A Reader*. New Delhi, India: Oxford University Press.

Jain, R.B. (2006). Opening Government for Public scrutiny: A Critique of Recent Efforts to make Governance in India more Transparent and Accountable. *Indian Journal of Public Administration*. 52(3), 56.

Kumar, A. (2011). Revitalizing Civil Society. *Third Concept*. 25(293), 58.

Mander, H. & Joshi, A. (1999). *The Movement for Right to Information in India: People's Power for the Control of Corruption*. New Delhi, India: Commonwealth Human Rights Initiative.

Mathur, B.P. (2005). *Governance Reform for Vision India*. New Delhi, India: MacMillan India Ltd.

Mishra, N. (2003). People's Right to Information Movement: Lessons from Rajasthan. Retrieved from https://www1.undp.org/content/dam/india/docs/people_right_information_movement_lessons_from_rajasthan.pdf

Mohan, S. (2009). Seekers, finders, keepers. Retrieved from http://old.tehelka.com/seekers-finders-keepers/

Naib, S. (2012). *The Right to Information Act, A Hand Book*. New Delhi, India: Oxford University Press.

Power to the People. (2005). *Economic & Political Weekly*. 40(21), 2115-2116.

Reddy, G.G. (2006). The Right to Information: An Analysis of its Evolution and Socio-Political Implications. *Punjab Journal of Politics*. 30(1), 73.

Roy, A. (2019). *The RTI Story, Power to the People.* New Delhi, India: Roli Books, Pvt. Ltd.

Roy, A., Dey, N. & Singh, S. (2010). Prabhash Joshi and the RTI Movement. *Mainstream.* 48(19). Retrieved from https://mainstreamweekly.net/article2016.html

Roy, B. (1996). Right to Information: Profile of a Grass Roots Struggle. *Economic and Political Weekly*. 31(19), 1120–1121.

Stuti. (n.d.). Evolution and Development of the Right to Information Act in India. Retrieved from http://www.legalserviceindia.com/legal/article-323-evolution-and-development-of-the-right-to-information-act-in-india.html

(1975) 4 SCC 428. Retrieved from https://indiankanoon.org/doc/438670/

(2004) 2 SCC 476. Retrieved from https://indiankanoon.org/doc/516862/

AIR 1982 SC 149. Retrieved from https://indiankanoon.org/doc/1294854/

CENTRE FOR P.I.L. & ORS. vs. UOI & ANR., W.P(C) 637/1998. Retrieved from https://indiankanoon.org/doc/104097615/

10.10 बोध प्रश्न के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1. आपके उत्तर में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:

- सुशासन के लिए सूचना का अधिकार अनिवार्य है। यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करके शासन की

गुणवत्ता को बढ़ाता है। सच्चे लोकतंत्र का निर्माण जागरूक, प्रबुद्ध और सशक्त नागरिकों की नींव पर होता है। भाग 10.1 का अध्ययन कीजिए।

- नागरिक समाज स्वयं लोगों द्वारा संचालित समाज है और इसमें गैर–राज्य हितधारक शामिल है, जैसेः गैर–सरकारी संगठन (NGO) स्वयं सहायता समूह, व्यावसायिक संघ, सामाजिक आंदोलन और विशेष हितों के समूह। भाग 10.2 और 10.3 का अध्ययन कीजिए

बोध प्रश्न 2

1. आपके उत्तर में निम्नलिखित शामिल होना चाहिएः

- ''जानने का अधिकार जीने का अधिकार है'' और ''हमारा पैसा, हमारे खाते'' जैसे नारों के साथ MKSS द्वारा सूचना के अधिकार की मांग के लिए चालीस दिन तक चलने वाला धरना (विरोध में बैठना) ऐतिहासिक बन गया। एन सी पी आर आई, सी एच आर आई, सी ई आर सी और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी सूचना के अधिकार आंदोलन की सफलता में योगदान दिया। भाग 10.4 का अध्ययन कीजिए।
- अदालती सुनवाई के रूप में, जन सुनवाई में लोगों को अपनी गवाही देने के लिए आमंत्रित किया गया था, जो प्रायः अधिकारिक अभिलेख (रिकॉर्ड) और लोगों के अनुभवों के बीच अंतर को प्रकट करता था। जनसुनवाई में अधिकारियों से विस्तृत दस्तावेज प्राप्त किए गए, खर्च के अभिलेख (रिकॉर्ड) को इकट्ठे हुए गांव के लोगों को सुनाया गया। MKSS ने इसे सूचना का अधिकार अधिनियम की मांग को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में पहचाना। भाग 10.4 का अध्ययन कीजिए।

बोध प्रश्न 3

1. आपके उत्तर में निम्नलिखित शामिल होना चाहिएः

- केंद्र में यूपीए सरकार के आने से सूचना का अधिकार आंदोलन को एक नया जीवन मिला। सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002, जिसे कभी अधिसूचित नहीं किया जा सकता था, को खारिज कर दिया गया। एन सी पी आर आई और उसके सहयोगियों के ठोस प्रयासों से सूचना का अधिकार अधिनियम का एक मसौदा तैयार किया गया और विचार के लिए राष्ट्रीय सलाहकार समिति को प्रस्तुत किया गया। नागरिक समाज संगठनों की मांगों और संसद की स्थायी समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। भाग 10.5 का अध्ययन कीजिए।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY